Board took up its construction and completed the work. After obtaining further technical information, the Power Telecommunications Co-ordinating Committee accorded its provisional approval for the energisation of the line. The final approval of the Committee will be issued on receipt of some further technical data from the Kerala State Electricity Board.

Expenditure on Indo-Pakistan War

270. Shri Badshah Gupta: Will the Minister of Finance be pleased to state the total expenditure incurred by Government in the last Indo-Pakistan conflict?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): It is difficult to compute the total expenditure incurred by the Government in the last Indo-Pak conflict. Even if it were possible to do, it would not be in public interest to divulge it.

Housing Loans given by L.I.C.

271. Shri V. V. Thevar: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Life Insurance Corporation of India gives loans to the policy holders and State Housing Boards;

(b) whether there is any difference in the rate of interest;

(c) if so, the difference with the reasons therefor; and

(d) whether there is any proposal to equalise the rate of interest to policy-holders to that given to the State Housing Boards?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The Life Insurance Corporation of India gives loans under the 'Own Your Home' Scheme to policy holders for construction or extension of houses and purchase of recently constructed houses. No loans are being given to State Housing Boards by the Corporation.

(b) to (d). Do not arise.

पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी

273. श्री [illegible] :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यह कब तक लागू की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). खाद्य व कृषि मंत्रालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्बन्धी कार्यकारी दल के सिंचाई उप-दल ने पहाड़ी इलाकों में सिंचाई के विकास के लिये प्रस्ताव बनाये हैं। इस उप दल की रिपोर्ट पर योजना आयोग के काम कर रही पहाड़ी क्षेत्र विकास सम्बन्धी स्टीयरिंग कमेटी ने अभी विचार करना है।

आय-कर से बचने के लिए जाली फर्मों की स्थापना

274. श्री बड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार के एक वकील द्वारा कर का अपवंचन करने के हेतु काल्पनिक नामों का प्रयोग करके फर्मों स्थापित करने के मामले का सरकार को पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी फर्मों की जांच के सम्बन्ध में आय-कर विभाग के